(ii) मध्यम आय वर्ग आवास योजना।

समाचार एजेन्सियो के कर्मचारी सहकारी आवास समितियां भी बना सकते हैं और एपेक्स कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटीज और आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास सिर्फ समाचार एजेन्सियां में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए कोई योजना नही है। किन्तु इसने दिल्ली प्रशासन से अधिकृत पत्रकारो और दिल्ली क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार से अधिकृत पत्रकारो एवं न्यूज कैमरामैनों तथा दैनिक समाचार पत्रों के उप-सम्पादको एवं रिपोर्टरो जो कि दिल्ली मे रह रहे हैं के लिए आम लोगो हेतु निर्मित फ्लैटों का 2 प्र०श० आरक्षण किया है। ये फ्लैट दिल्ली विकास प्राधिकरण के अग्रिम (एडवान्स) पजीकरण योजनाओ के अन्तर्गत पजीकृत व्यक्तियो को आवंटित किए जाते हैं।

Irrigation Potential in States

*457. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some States of the Union have immense irrigation potential but it is not being adequately exploited and used;

(b) if so, whether Central Government propose to help augment the irrigation facilities in such States,

(c) if so, how and when; and

(d) if not, why not?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The total irrigation potential in the country is at present assessed as 107 m.ha. This, however, is likely to increase with the advancement of technology economical use of water and possibilities of diversion of water from areas having surplus to deficit areas. The irrigation potiential likely to be created by the end of 1977-78 is 54 m. ha. which is 50 per cent of the ultimate. The level of exploitation and its utilisation, however, varies from State to State.

(b) to (d). Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, formulated and implemented by the State Governments. The Central assistance is in the form of block loans/grants which is not related to any sector of development or scheme.

It is envisaged that most of the balance irrigation potential would be created during the next 15 years. The next Five Year Plan (1978—83) envisages creation of additional irrigation potential of 17 m. ha. This will be mainly in the States where there is large scope for further development of irrigation potential.

काल-पात्र

*458. श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काल-पात्र में रखे लेख (स्क्रोल) के ब्यौरे का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमे कौन कौन सी बातें ठीक नही हैं अथवा बढ़ा चढ़ा कर कही गई है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (ग). काल पात्र सम्बन्धी संसदीय समिति द्वारा

प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच की जा रही है और इसे काल पात्र से पुनः प्राप्त किए गए 1947 से 1972 तक की घटनाओं के तिथि पत्र और भारतीय इतिहास के 10,000% शब्दों के वृत्तान्त की प्रति के साथ यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा। उसके बाद यह निर्णय माननीय सदस्यों को करना होगा कि क्या इसमें गलत अथवा बढ़ा चढ़ा कर कही गई कोई बात शामिल है।

आदिवासी क्षेत्रों में निरक्षरता समाप्त करना

462. श्री श्याम लाल धुर्वे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार देश के आदिवासी क्षेत्रों से निरक्षरता समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग). आदिवासी क्षेत्रों सहित, देश से निरक्षरता के उन्मूलन के लिए सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण तथा प्रौढ़ शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। अगले पांच वर्षों के दौरान औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत 320 लाख अतिरिक्त बच्चों को तथा प्रस्ताव के अनुसार 2 अक्तूबर, 1978 से प्रारम्भ किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम द्वारा 15–35 आयु वर्ग के लगभग 10 करोड़ बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय के स्वीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक स्वीकृत 116 परियोजनाओं में विशेष शैक्षिक प्रगति के कार्यक्रम भी शामिल हैं।

Wheat Farming in Andhra Pradesh

*464. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether wheat farming is being popularised in Andhra Pradesh;

(b) if so, with what result; and

(c) whether any rice or millet growing area has been diverted to wheat growing?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir, Though wheat is not an important crop in Andhra Pradesh, it is getting popular year by year.

(b) The area under wheat in the State has increased from 13,800 hectares in 1967-68 to 26,300 hectares in 1975-76. Similarly, the production of wheat has increased from 2,700 tonnes to 21,500 tonnes during the same period. However, both area and production of wheat in the State declined to 23,800 hectares and 14,600 tonnes respectively, during 1976-77, owing to unfavourable weather conditions.

(c) The increase in wheat area in Andhra Pradesh is mostly due to increase in gross cropped area.

Loni Road Residential Scheme, Delhi

*465. SHRI KISHORE LAL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the period of Emergency land under Loni Road Residential Scheme of Delhi Development Authority was neither acquired by Delhi Administration nor handed over to DDA;